कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री (डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी) : (क) और (ख) जी, हां । अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में व्यापक संशोधन करने के संबंध में, इसी प्रकार के अन्य प्रस्तावों के साथ-साथ दक्षिणी राज्यों में अनुसूचित जातियों की सूची में खटीक समुदाय को शामिल करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है । इसके अलावा संविधान की धारा 341(2) और 342(2) को ध्यान में रखते हुये अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की वर्तमान सूचियों में संशोधन केवल संसद के अधिनियम के द्वारा ही किया जा सकता है ;

(ग) हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, और उत्तर प्रदेश राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और दिल्ली की अनुसूचित जातियों की सूची में खटीक समुदाय को शामिल कर लिया गया है । अनुसूचित जातियों की वर्तमान सूची में सोनकर नहीं आते ।

Distribution of imported butter

2178. SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the imported butter found unfit for human consumption has now been distributed to Dairy plants in organised and Cooperative Sectors, and if so, for what purpose it was used; and

(b) whether any irregularities in the distribution have been noticed, and if so, what action has been taken in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI YOGENDRA MAKWANA): (a) and (b) Imported butter found unfit for human consumption has not been distributed by the National Dairy Development Board to Dairy plants in organised and Co-operative sector.

आवश्यक वस्तुओं के थोक/खुदरा मूल्य

2179. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले 12 महीनों के दौरान आवश्यक वस्तुओं के महीनेवार थोक और खुदरा मूल्य क्या थे ;

(ख) पिछले वर्ष में इसी अवधि के दौरान विद्यमान मूल्यों की तुलना में यह मूल्य कितने हैं ; और

(ग) यदि मूल्यों में वृद्धि हुई है तो इस मूल्य वृद्धि का गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों और निर्धारित आय वाले वर्ग के व्यक्तियों पर क्या असर पड़ा ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना अनुबंध--I [देखिए परिशिष्ट CXLIV अनुपत्र सं० 96] और II [देखिए परिशिष्ट CXLIV अनुपत्र सं० 97] पर दिए गए विवरणों में दी गई है ;

(ग) पिछले 12 महीनों के दौरान कई आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में कुछ वृद्धि हुई है । गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों तथा नियत आय वर्ग के लोगों पर

इसका कुछ प्रभाव पड़ेगा । तथापि, सरकार द्वारा मूल्य वृद्धि के असर को कम से कम करने के लिये कई उपाय किये गये हैं । इनमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसके माध्यम से कुछ प्रमुख आवश्यक वस्तुएं आम लोगों को उचित मूल्यों पर वितरित की जाती हैं, को मजबूत करना तथा उसका विस्तार करना भी शामिल है । ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब लोगों को विशेष योजनाओं के तहत सस्ते मूल्यों पर खाद्यान्न वितरित किये जाते हैं । सहकारी तंत्र द्वारा बहुत सी आवश्यक वस्तुएं उचित मूल्यों पर बेंची जाती हैं । अवांछित मूल्यवृद्धि को रोकने की दृष्टि से कई राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा जमाखोरी, कालाबाजारी आदि के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा रही है ।

Steel stockyards at Jabalpur and Bhopal

2180. SHRI AJIT P. K. JOGI: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether a decision was taken by the Steel Authority of India Limited to establish steel stockyards at Jabalpur and Bhopal in Madhya Pradesh;

(b) if so, what are the reasons that the decision has not been implemented;

(c) whether it is a fact that the stockyard established in Indore as far back as in 1969, is now being shifted to some other place;

(d) if so, what are the reasons therefor; and

(e) whether the demand of steel at Indore was found to be inadequate?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI M. L. FOTEDAR): (a) and (b) SAIL has opened a stockyard at Jabalpur. No decision has, however, yet been taken to open a stockyard at Bhopal.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

(e) The demand potential at Indore area has been found adequate by SAIL for running a stockyard.

Selection of T.V. serials

2181. SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to refer to reply to Starred Question 8 given in the Rajya Sabha on the 6th November, 1987 and state what are the number of applications now pending with the Doordarshan for different T.V. serials?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI AJIT PANJA): Doordarshan stopped acceptance of proposals for T.V. serials with effect from 7.5.1986. All the proposals received till then were considered and decision was communicated to the concerned parties. As on date, no proposal for serial is pending consideration with Doordarshan. However, appeals for re-consideration of the rejected proposals are received from time to time. The review of these appeals is a continuous process.

Low cost sanitation scheme for rural areas

2182. SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether a low cost sanitation scheme for rural areas has been submitted to Government;

(b) if so, what are its main features;